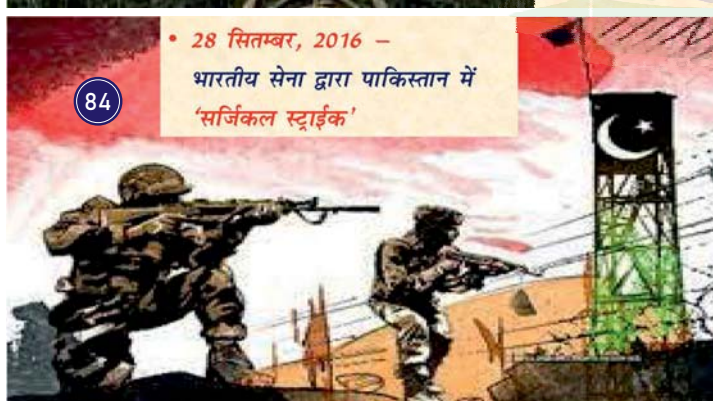
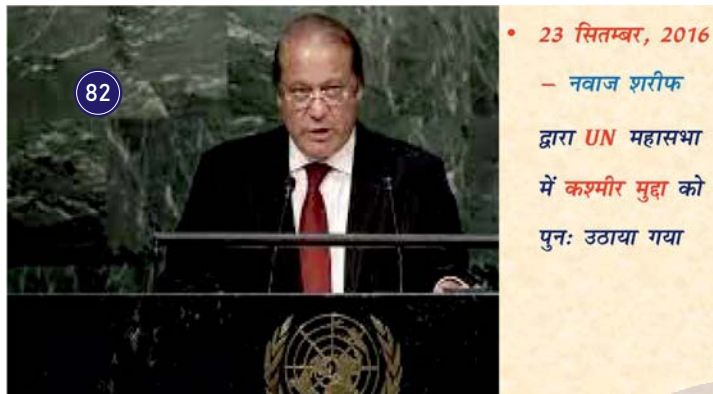
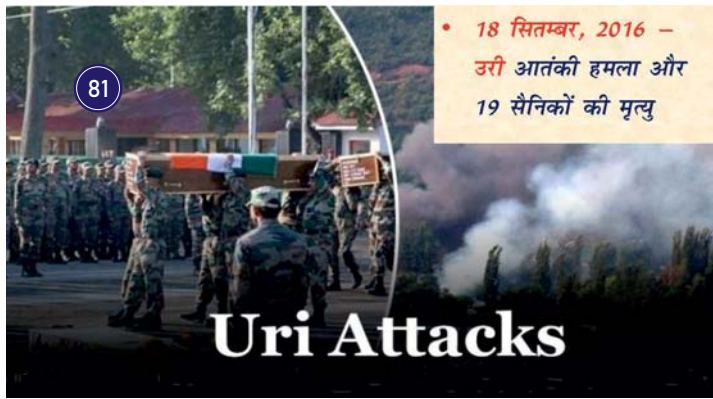






91

आतंकियों का काल: ऑपरेशन ऑल आउट

- 23 मई 2019 – भारतीय सेना द्वारा कश्मीर में 'ऑपरेशन ऑल आउट' तेज – आतंकी जाकिर मुसा मारा गया – (अंसार-गजावत-उल-हिन्द – 2014 में अलकायदा)



96

2024

जम्मू-कश्मीर में TRF, जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स, कश्मीर टाइगर्स आदि नये आतंकी संगठनों का उद्भव तथा Hybrid Militants द्वारा आतंकी हमला तेज

- 5 अगस्त 2019 – जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जम्मू और कश्मीर में 370 हटाया गया –
फलतः जम्मू कश्मीर भारत सरकार के नियंत्रण में – जम्मू-कश्मीर एक केन्द्र शासित प्रदेश तथा लक्षाद्वय दूसरा केन्द्र शासित प्रदेश



92

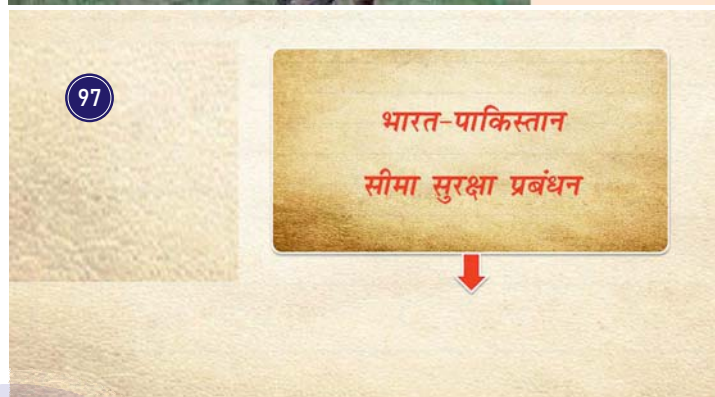
अनुच्छेद
370



93

दिसम्बर 2020 में DDC चुनाव

- 280 सीटों पर 51.42% मतदान
- कश्मीर में गुपकार गठबंधन तथा जम्मू में भाजपा की जीत



97

भारत-पाकिस्तान
सीमा सुरक्षा प्रबंधन



98

A. सीमा सुरक्षा प्रबंधन :
भौतिक प्रबंधन



94

11 दिसम्बर 2023

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार द्वारा 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्र-शासित प्रदेशों में विभाजित करने के निर्णय को सही ठहराया



95

अक्टूबर 2024 जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं कांग्रेस गठबंधन की जीत तथा उमर अब्दुल्ला CM (कुल 90 सीटों पर चुनाव – NC-42 BJP-29)



99

1. BSF & Army की तैनाती तथा आधुनिकतम हथियारों की तैनाती



100

SMART BORDER

- नाइट विजन उपकरण
- सीसीटीवी के कैमरे
- लेजर दीवार
- ड्रोन

सर्वांगीण राइफल
हार्ड पावर टेलिस्कोप
हैंड-हेल्ड थर्मल इमेजर्स
ग्राउंड सेन्सर

2. Smart Fencing / बाड़बंदी - 2078 km;
- सीमा सुरक्षा चौकी (BOP) - 736 (ताकि बीच की दूरी 3.5 km हो सके);
- तेज रोशनी लाइट (2078 km)
- निगरानी हेतु आधुनिक उपकरणों का प्रयोग

3. आकाश, बराक-8, पृथ्वी, अग्नि, शौर्य, नाग, हेलिना आदि मिसाइलों की तैनाती



Project Trishul

4. पंजाब से लगी भारत-पाकिस्तान सीमा पर **Laser Beam Detection System** एवं **Predator Drone** की तैनाती

5. 'प्रोजेक्ट कुश' के तहत, इजरायल के 'आयरन डोम सिस्टम' की तर्ज पर भारत में 'एयर डिफेंस सिस्टम' का विकास और 'S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम' की तैनाती

6. ड्रोन खतरे से निपटने हेतु विशेष प्रयास

1. ड्रोन खतरे से निपटने की क्षमताओं का विकास; जैसे- सुरक्षा बलों द्वारा गश्त, राडार, जैमर, ड्रोनरोधी हथियारों की तैनाती
2. ड्रोन फोरेंसिक का प्रयोग तथा दिल्ली में एक आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना
3. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर कमांड-एण्ड-कंट्रोल सिस्टम के साथ कैमरे, सेंसर और अलार्म से लैस एकीकृत निगरानी तकनीक की स्थापना
4. 'एंटी-रॉग ड्रोन प्रौद्योगिकी समिति' की स्थापना
5. जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण
6. 'एंटी-ड्रोन सिस्टम' की खरीद एवं सीमा पर तैनाती
7. इस संदर्भ में **DRDO** के साथ सहयोग और पृथक ड्रोन नीति के निर्माण का प्रयास
8. खुफिया नेटवर्क एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय

7. सीमावर्ती सड़कों का निर्माण



8. सीमा पर तस्करी एवं घुसपैठ के विरुद्ध अभियान एवं 'सर्जिकल स्ट्राइक' (29 Sept. 2016 & 26 Feb. 2019)



घुसपैठ के विरुद्ध तीन स्तरीय सुरक्षा रणनीति

1. लाइन ऑफ कंट्रोल
2. रिसेप्शन एरिया
3. हिंटरलैंड



आतंकवाद के विरुद्ध 'ऑपरेशन ऑल-आउट'

नवम्बर 2024 तस्करी पर नियंत्रण हेतु राजस्थान में Anti-narcotics Task Force का गठन



भारत पाकिस्तान सीमा प्रबंधन : सर्जिकल स्ट्राइक 2.0



26 Feb 2019 - भारतीय वायु सेना के 12 मिग 2000 जेट ने पाकिस्तान के बालकोट में जैश-ए-मोहम्मद संघलित आतंकवादी शिविर पर हमला किया। और लगभग 200-300 आतंकी मारे गए।

विमुद्रीकरण - 2016



8 Nov. 2016 - भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा



13. जम्मू-कश्मीर में विश्वास बहाली की दिशा में किए गए प्रयास



9. Infrastructure Management Scheme

- सीमा पर बाड़बंदी एवं स्मार्ट बाड़बंदी
- बॉर्डर फ्लड लाइट
- सीमा पर चौकी का निर्माण
- सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण
- सीमा पर हेलीपैड का निर्माण



14. Border Area Development Programme (1986-87 में प्रारंभ)

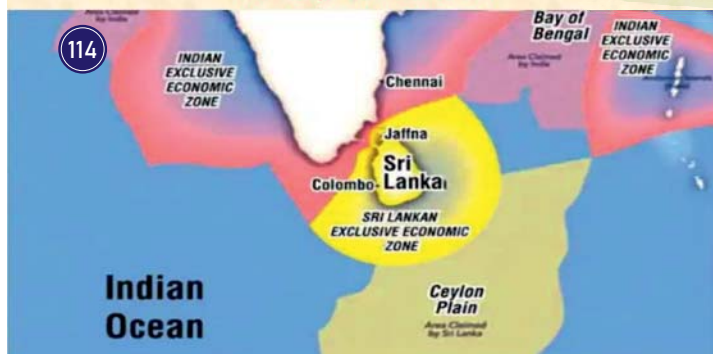
- अन्तराष्ट्रीय सीमा के 50 किमी. के अन्दर रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करना
- सीमा पर स्थित गाँवों का विकास करना
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 राज्यों के 111 सीमावर्ती जिले शामिल



10. सीमावर्ती क्षेत्र में सैन्य अभ्यास
- ऑपरेशन 'अलर्ट' - 21 Jan. - 28 Jan. 2023
 - भारत-फ्रांस नौसेना अभ्यास 'वरुण' - Sept. 2023
 - ऑपरेशन 'सर्द हवा' - Jan. 2024
 - भारत-अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास - Sep. 2024
 - वायु सेना अभ्यास 'गगन शक्ति' - Sept. 2024



11. समद्री सीमा का प्रबंधन



12. 5 अगस्त 2019 - जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जम्मू और कश्मीर में 370 हटाया गया -
फलतः जम्मू-कश्मीर भारत सरकार के नियंत्रण में - जम्मू-कश्मीर में एक तरफ विकास की प्रक्रिया तीव्र तो दूसरी तरफ 'ऑपरेशन ऑल आउट' के तहत आतंकियों का सफाया



1. 1966 - ताशकंद समझौता



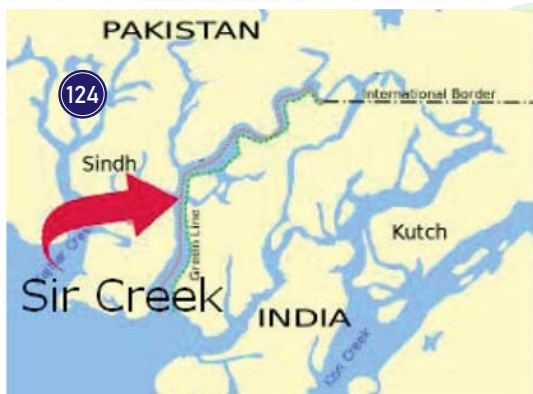
2. 1972 -
शिमला
समझौता



3. 1999 - लाहौर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर



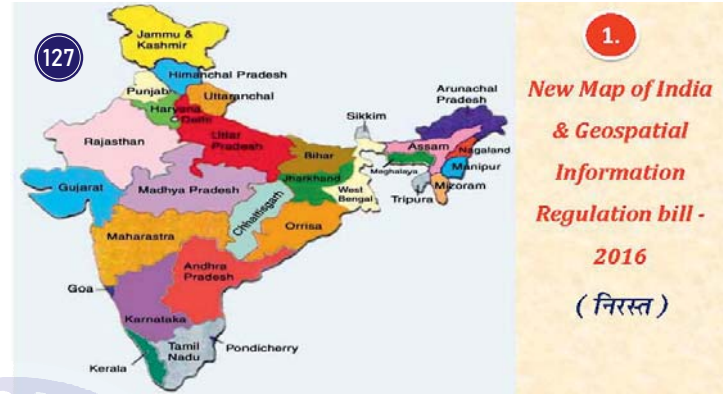
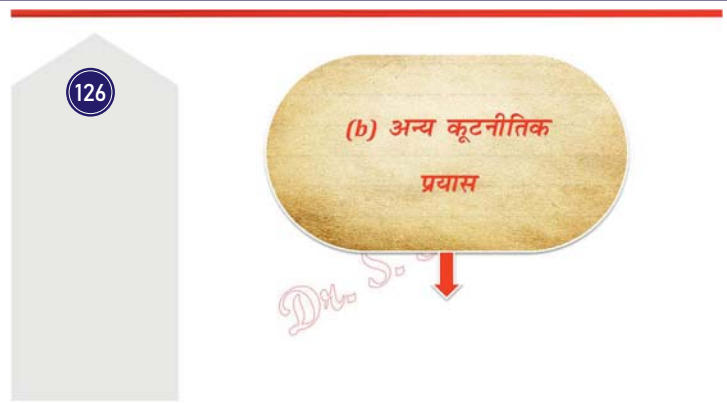
4. 2004 -
इस्लामाबाद
घोषणापत्र
पर हस्ताक्षर



5. 2016 तक
- सीमा
विवाद को
सुलझाने हेतु
निरन्तर वार्ता
एवं प्रयास



6. 24 Oct. 2019 - करतारपुर कॉरिडोर समझौता



1.
New Map of India
& Geospatial
Information
Regulation bill -
2016
(निरस्त)



2.
15 अगस्त-2016 -
भारत की
बलूचिस्तान-गिलगिट
- POK रणनीति



3.
14 सितम्बर - 2016
पहली बार भारत द्वारा
बलूचिस्तान -
गिलगिट- POK
में मानवाधिकार
उल्लंघन के मुद्दे को
संयुक्त राष्ट्र में उठाया
गया



4. विभिन्न अंतराष्ट्रीय मंचों पर (UN, G-20, BRICS etc) भारत द्वारा
पाकिस्तान को आतंकवादियों को समर्थन देने वाले देश के
रूप में मान्यता दिलवाने का प्रयास

131

5. अमेरिका के साथ विभिन्न समझौते (LEMOA-2016; COMCASA-2018; BECA-2020) के द्वारा निकटता में वृद्धि



136



2.

सिंधु जल संधि, नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर, 1960 में हुई एक संधि है। जिसके द्वारा दोनों देशों को पानी के उपयोग का प्रावधान किया गया है

132



6.

25 नवम्बर 2016 - भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौता समाप्त करने पर विचार करने की घोषणा (रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं)



137

सिंधु जल समझौता 1960 के प्रमुख बिन्दु



133

7. 24 फरवरी 2024 - रावी नदी पर शाहपूर कंडी बैराज बंद और रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोका गया



138



1.

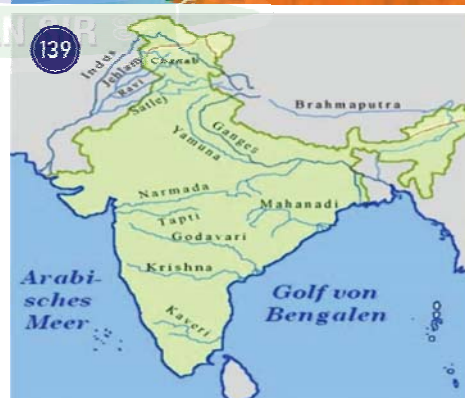
सिंधु नदी / बेसिन की सहायक नदियों को - पूर्वी नदियों [सतलज, व्यास, रावी] तथा पश्चिमी नदियों [झेलम, चेनाब, सिंधु] में विभाजित किया गया

134

सिंधु जल विवाद



139



2.

पूर्वी नदियों का 100% पानी भारत के लिए तथा पश्चिमी नदियों का 80% पानी पाकिस्तान के लिये होगा

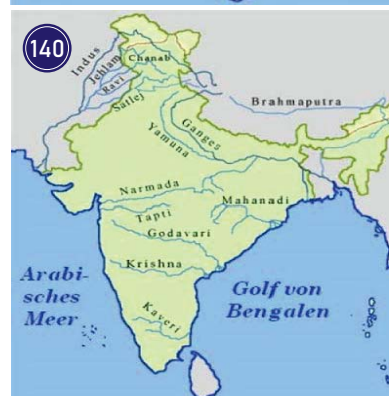
135



1.

सिंधु नदी का इलाका 11.2 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत- जिसका 47% पाकिस्तान में, 39% भारत में, 8% चीन में, 6% अफगानिस्तान में है और 30 करोड़; लोग इस क्षेत्र के आस-पास रहते हैं। पाक की 2.6 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई इस पर निर्भर है

140



3. पश्चिमी नदियों के पानी को भारत भी सीमित इस्तेमाल कर सकता है [लगभग 20%]/36 लाख एकड़ फीट पानी जमा करने का अधिकार
4. भारत पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजना बना सकता है परंतु पानी रोक नहीं सकता
5. 'सिंधु आयोग' का प्रावधान



141

- **Sept. 2016** में - भारत द्वारा सिंधु जल समझौता के तहत अपने हिस्से की पानी का पूरा इस्तेमाल करने का निर्णय तथा चेनाब एवं झेलम नदी पर 2 जल विद्युत परियोजना निर्माण का निर्णय-
 - (i) रातले (850 मेगावाट) तथा
 - (ii) किशनगंगा (330 मेगावाट परियोजना) - पाकिस्तान द्वारा विरोध
 - (iii) पुनः भारत द्वारा **शाहपुर कंडी परियोजना** का निर्माण **Sept. 2018** से तथा उक्त परियोजना (**July, 2017** को मंजूरी) प्रारंभ

142

- **25 Dec. 2016** - पाकिस्तान द्वारा इस मामले में 'विश्व बैंक' को हस्तक्षेप करने की अपील
- **1 August 2017** - विश्व बैंक द्वारा 'फैक्टरशीट' जारी और कहा गया कि- संधि के अनुसार भारत इन नदियों का पानी किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकता है और **पनबिजली परियोजना** बना सकता है

143

- **29 Dec 2017** - रावी की सहायक नदी पर उक्त बहुदेशीय परियोजना निर्माण का निर्णय तथा **7 May 2018** को पंजाब एवं हरियाणा सरकार द्वारा रावी एवं ब्यास नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने का निर्णय
- **19 August 2018** - इमरान खान द्वारा सिंधु जल विवाद पर पुनः **वर्ल्ड बैंक** जाने का निर्णय

146



147

- **30 अगस्त 2024** - भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिये पुनः पाकिस्तान को नोटिस जारी



148

सिंधु जल समझौता -
समीक्षा

144

- **14 Feb 2019** को पुलवामा हमले के बाद (**9 May 2019** को) नीतिन गडकरी द्वारा बयान कि - सिंधु जल संधि के तहत भारत अपने हिस्से का पानी पाक को नहीं देगा [**Water Surgical Strike**] = पाक का बयान कि हम इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जायेंगे
- **27 January 2023** - भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि में संशोधन हेतु पाकिस्तान को नोटिस जारी

149

जल समझौता तोड़ने का लाभ

1. पाकिस्तान पर दबाव संभव
2. **J & K** की जल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति संभव

145

- **24 फरवरी 2024** - रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज बंद और रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोका गया



150

जल समझौता तोड़ने का नुकसान

1. पाक की जनता को प्रत्यक्ष नुकसान से अतिवाद वृद्धि तथा भारत के विरुद्ध जन-भावना के विकास की संभावना फलतः भारत को नुकसान
2. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में कमी
3. बाढ़ की आशंका